राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी.आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 12956/2020

दिनेश पुत्र लालू, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी मांडविया मोदर पुलिस थाना बिछीवाड़ा, जिला डूंगरपुर (वर्तमान में जिला जेल डूंगरपुर में बंद)

----याचिकाकर्ता

बनाम

राजस्थान राज्य, पी.पी. के माध्यम से

----प्रतिवादी

एस.बी.आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 13088/2020

जगदीश पुत्र बालू राम, उम्र लगभग 24 वर्ष, जाति जाट, निवासी जाखड़ों की ढाणी, गोदावास, थाना भोपालगढ़, जिला जोधपुर।
(वर्तमान में सेंट्रल जेल, जोधपुर में बंद हैं)

----याचिकाकर्ता

बनाम

राज्य, पी.पी. के माध्यम से

----प्रतिवादी

एस.बी.आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 13204/2020

सीता राम पुत्र श्री हीरा राम, उम्र लगभग 30 वर्ष, जाति जाट, निवासी ग्राम तेजरासर, तहसील और जिला बीकानेर। (वर्तमान में केन्द्रीय कारागार बीकानेर में बंद है)।

----याचिकाकर्ता

बनाम

राजस्थान राज्य, पी.पी. के माध्यम से

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ताओं के लिए: श्री आर.एस.चौधरी, श्री विनीत जैन और श्री जितेंद्र ओझा

प्रतिवादी(ओं) के लिए: श्री महिपाल बिश्नोई, पीपी और श्री गौरव सिंह पीपी, राज्य के लिए।

माननीय न्यायाधिपति डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी

<u>आदेश</u>

<u>रिपोर्टेबल</u>

<u>20/11/2020 को आरक्षित</u>

<u>02/12/2020 को सुनाया गया</u>

1. कोविड-19 के हमले के मद्देनजर, न्यायालय में मामलों की सुनवाई के दौरान अत्यधिक सावधानी बरती जा रही है।

2. इस न्यायालय ने रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

3. याचिकाकर्ताओं को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/20 और शस्त्र अधिनियम की धारा 3/25 **(सीआरएलएमबी संख्या 12956/2020)** के तहत अपराध के लिए पुलिस स्टेशन बिछीवाड़ा, जिला डूंगरपुर की एफआईआर संख्या 321/2020 के संबंध में गिरफ्तार किया गया है। शस्त्र अधिनियम की धारा 3/25 और 5/25 **(सीआरएलएमबी संख्या 13088/2020)** के तहत अपराध के लिए पुलिस स्टेशन उदयमंदिर, जोधपुर की एफआईआर संख्या 296/2020 और; शस्त्र अधिनियम की धारा 3/25 **(सीआरएलएमबी संख्या 13204/2020)** के तहत अपराध के लिए पुलिस स्टेशन, जय नारायण व्यास कॉलोनी, बीकानेर की एफआईआर संख्या 266/2020। उन्होंने

सीआरपीसी की धारा 439 के तहत ये जमानत याचिकाएं दायर की हैं।

4. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील श्री आर.एस.चौधरी और श्री जीतेन्द्र ओझा ने एक कानूनी मुद्दा उठाया कि शस्त्र अधिनियम, 1959 (इसके बाद इसे 'अधिनियम' के रूप में भी जाना जाता है) के तहत सभी अपराध, आपराधिक प्रक्रिया संहिता (संक्षिप्तता के लिए, 'सी.आर.पी.सी.') की धारा 436 के साथ पढ़े गए अधिनियम की धारा 37 के पढ़ने मात्र के आधार पर जमानती हैं।

5. इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने अधिनियम के तहत अपराधों को जमानती होने की बात कहते हुए, शस्त्र अधिनियम के तहत आरोपी-याचिकाकर्ताओं के लिए जमानत के पूर्ण हकदार होने का दावा किया।

6. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने यह स्पष्ट किया कि वे योग्यता के आधार पर जमानत आवेदनों पर दबाव नहीं डाल रहे हैं, बल्कि केवल उपरोक्त कानून बिंदु पर प्रस्तुतियाँ दे रहे हैं, क्योंकि, यदि शस्त्र अधिनियम के तहत अपराध इस न्यायालय द्वारा जमानती प्रदान किए जाते हैं, तो याचिकाकर्ता केवल शस्त्र अधिनियम के मामलों में मामले की गुणवत्ता पर जाए बिना जमानत के हकदार बन जाएंगे।

7. कुछ समय तक याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील को सुनने के बाद, वर्तमान मामलों में शामिल उपरोक्त कानूनी मुद्दे के अधिक महत्व को

देखते हुए, जिसमें दिए जाने वाले किसी भी फैसले से बड़ी संख्या में आरोपी व्यक्तियों के प्रभावित होने की संभावना है, इस न्यायालय ने मौखिक रूप से बड़े पैमाने पर बार को अपने बहुमूल्य विचार व्यक्त करने और मुद्दे पर निर्णय लेने के उद्देश्य से अपने तर्क आगे बढ़ाने के लिए निमंत्रण दिया। इस तरह के मौखिक निमंत्रण को उत्साहपूर्वक स्वीकार कर लिया गया। तदनुसार, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील और नियुक्त विद्वान लोक अभियोजक के अलावा, श्री विनीत जैन, विद्वान अधिवक्ता और श्री गौरव सिंह, विद्वान लोक अभियोजक ने, अपनी सामान्य स्पष्टता के साथ, उपरोक्त कानूनी मुद्दे पर विस्तार से अपनी बात आगे बढ़ाते हुएइस न्यायालय को संबोधित किया है।

8. याचिकाकर्ताओं और अन्य विद्वान वकीलों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि इसमें शामिल मुद्दे का निर्णय इस माननीय न्यायालय की जयपुर पीठ द्वारा **एस.बी. क्रिमिनल विविध द्वितीय जमानत आवेदन संख्या 6746/2009 (रामविलास @ बिल्लू बनाम राजस्थान राज्य,** 02.09.2009 को निर्णय) में पहले ही कर दिया गया था। उक्त निर्णय का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

> "4. विद्वान लोक अभियोजक ने निष्पक्ष रूप से स्वीकार किया है कि शस्त्र अधिनियम की धारा 37 के प्रावधानों के

तहत, अधिनियम के तहत किसी भी अपराध को जमानती बना दिया गया है।

5. बार में की गई दलीलों पर विचार करने और रिकॉर्ड पर उपलब्ध प्रासंगिक सामग्री का अवलोकन करने के बाद, मैं शस्त्र अधिनियम की धारा 37 को पुन: प्रस्तुत करने के लिए उपयुक्त महसूस करता हूं जो इस प्रकार है:

"**37. गिरफ़्तारी और तलाशी.**—इस अधिनियम में जैसा अन्यथा प्रावधानित है उसे छोड़कर,—

(ए) इस अधिनियम के तहत या इसके तहत बनाए गए किसी भी नियम के तहत की गई सभी गिरफ्तारियां और तलाशी क्रमशः आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)] के प्रावधानों के अनुसार की जाएंगी, जो इस कोड के तहत की गई गिरफ्तारियों और तलाशी से संबंधित हैं।

(बी) इस अधिनियम के तहत गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति और किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जब्त किए गए हथियार या गोला-बारूद, जो मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी नहीं है, को बिना देरी किए निकटतम पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को सौंप दिया जाएगा और वह अधिकारी-

(i) या तो उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने के लिए जमानतदारों के साथ या उसके बिना बांड भरने पर

रिहा कर देगा और जब्त की गई चीजों को मजिस्ट्रेट के सामने उस व्यक्ति की उपस्थिति तक अपनी हिरासत में रखेगा, या

(ii) यदि वह व्यक्ति बांड निष्पादित करने और, यदि आवश्यक हो, पर्याप्त ज़मानत देने में विफल रहता है, तो उस व्यक्ति और उन चीज़ों को बिना किसी देरी के मजिस्ट्रेट के सामने पेश करें।

6. इस धारा में परिकल्पना की गई है कि यदि इस अधिनियम के तहत किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और कोई हथियार या गोला-बारूद जब्त किया जाता है, तो वह व्यक्ति मजिस्ट्रेट के समक्ष अपनी उपस्थिति के लिए जमानत के साथ या उसके बिना बांड निष्पादित करने पर रिहा होने का हकदार है। आरोपी को मजिस्ट्रेट के पास केवल उस स्थिति में ले जाया जाएगा जब आरोपी जमानत बांड प्रस्तुत करने में विफल रहता है। शस्त्र अधिनियम की धारा 37 के प्रावधान अनिवार्य हैं और सीआरपीसी की धारा 436 के प्रावधानों के अनुरूप हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ये प्रावधान निचली अदालत की नज़रों से बच गए हैं।

7. जैसा कि स्पष्ट है, याचिकाकर्ताओं पर शस्त्र अधिनियम

की धारा 3/25 के तहत अपराध में शामिल होने का आरोप है। माना कि यह अपराध जमानतीय है। जमानती अपराध के आरोपी व्यक्ति को जमानत देना दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 436 के प्रावधानों द्वारा शासित होता है। . . . ।"

9. इस समय, इसके विपरीत, राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान लोक अभियोजक श्री महिपाल बिश्नोई और श्री गौरव सिंह ने प्रस्तुत किया कि राम विलास @ बिल्लू (सुप्रा) के फैसले में, माननीय न्यायालय ने शस्त्र अधिनियम के तहत अपराध को अधिनियम की धारा 37 के आधार पर जमानती माना है, और कानूनी स्थिति के गुणों पर विचार नहीं किया है, ताकि शस्त्र अधिनियम के तहत अपराध को जमानती अपराध माना जा सके।

9.1 विद्वान लोक अभियोजक ने आगे कहा कि माननीय न्यायालय ने, राम विलास उर्फ बिल्लू (सुप्रा) के मामले का फैसला करते हुए, केवल विद्वान लोक अभियोजक की स्वीकारोक्ति के आधार पर जमानत आवेदन की अनुमति दी है कि शस्त्र अधिनियम के तहत अपराध अधिनियम की धारा 37 के अनुसार जमानती थे, और इसलिए, याचिकाकर्ता को जमानत देना सीआरपीसी की धारा 436 की भावना के अनुसार अनिवार्य था।

9.2 विद्वान लोक अभियोजक ने इस प्रकार प्रस्तुत किया कि शस्त्र अधिनियम के तहत अपराध के जमानती होने का प्रश्न, जिसे राम विलास @ बिल्लू (सुप्रा) के फैसले में बिल्कुल भी नहीं ठहराया गया है, खुला रहता है और वास्तव में एस.बी. क्रिमिनल विविध जमानत आवेदन संख्या 13027/2014 (अमर सिंह नरूका बनाम राजस्थान राज्य, 02.12.2014 को निर्णय लिया गया) में इस माननीय न्यायालय की जयपुर पीठ द्वारा दिए गए एक अन्य फैसले में संबोधित किया गया है, जिसका प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

> *"मैंने संबंधित पक्षों की ओर से की गई दलीलों, मेरे अवलोकन के लिए उपलब्ध कराई गई सामग्री के साथ-साथ याचिकाकर्ता की ओर से संबंधित कानूनी प्रावधानों और मामले के कानून पर विचार किया है।*
>
> *. . . . . .*
>
> *अब, अधिनियम की धारा 37 को उद्धृत करना उपयोगी है, जो इस प्रकार है:*
>
> *"गिरफ्तारी और तलाशी।-इस अधिनियम में अन्यथा प्रदान किए गए को छोड़कर,-*
>
> *(ए) इस अधिनियम के तहत या इसके तहत बनाए गए किसी भी नियम के तहत की गई सभी गिरफ्तारियां और*

तलाशी क्रमशः आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)] के प्रावधानों के अनुसार की जाएंगी, जो इस कोड के तहत की गई गिरफ्तारियों और तलाशी से संबंधित हैं;

(बी) इस अधिनियम के तहत गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति और किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जब्त किए गए हथियार या गोला-बारूद, जो मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी नहीं है, को बिना देरी किए निकटतम पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को सौंप दिया जाएगा और वह अधिकारी-

(i) या तो उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने के लिए जमानतदारों के साथ या उसके बिना बांड भरने पर रिहा कर देगा और जब्त की गई चीजों को मजिस्ट्रेट के सामने उस व्यक्ति की उपस्थिति तक अपनी हिरासत में रखेगा, या

(ii) यदि वह व्यक्ति बांड निष्पादित करने और, यदि आवश्यक हो, पर्याप्त ज़मानत देने में विफल रहता है, तो उस व्यक्ति और उन चीज़ों को बिना किसी देरी के मजिस्ट्रेट के सामने पेश करें।

अधिनियम की धारा 37 के खंड (ए) में प्रावधान है कि अधिनियम के तहत या उसके तहत बनाए गए किसी भी

नियम के तहत की गई सभी गिरफ्तारियां और तलाशी उस संहिता के तहत की गई गिरफ्तारी और तलाशी से संबंधित संहिता के प्रावधानों के अनुसार की जाएंगी। इस प्रकार, अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी या तलाशी और जब्ती के लिए अधिनियम के तहत कोई विशेष प्रक्रिया प्रदान नहीं की गई है। खंड (बी) में प्रावधान है कि इस अधिनियम के तहत किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है या कोई हथियार या गोला-बारूद किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जब्त किया गया है जो मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी नहीं है, उसे बिना देरी किए निकटतम पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को सौंप दिया जाएगा और वह पुलिस अधिकारी या तो उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने के लिए जमानतदार के साथ या उसके बिना बांड भरने पर रिहा कर देगा और जब्त की गई चीजों को उस व्यक्ति के मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने तक अपनी हिरासत में रखेगा।

उपरोक्त प्रावधान पर बारीकी से नजर डालने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि यह प्रावधान तभी लागू होता है जब किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी के अलावा

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा गिरफ्तार किया जाता है और केवल उस स्थिति में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को बिना किसी देरी के निकटतम पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को सौंप दिया जाना आवश्यक है। मेरा मानना है कि यदि किसी व्यक्ति को किसी पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट यानी कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया जाता है, तो प्रावधान लागू नहीं होता है और यह आवश्यक नहीं है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को निकटतम पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को सौंप दिया जाए। इसके अलावा, अधिक से अधिक यह प्रावधान यह प्रदान करता है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा केवल जमानत के साथ या उसके बिना बांड निष्पादित करने पर मजिस्ट्रेट के समक्ष उसकी उपस्थिति के सीमित उद्देश्य के लिए रिहा किया जाएगा और केवल इसलिए किसी पुलिस अधिकारी के प्रभारी अधिकारी को ऐसे व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होने के सीमित उद्देश्य के लिए रिहा करने का अधिकार दिया गया है, ***मेरे विचार में, यह नहीं कहा जा सकता कि अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध या कोई भी अपराध जमानतीय है। मेरा मानना है कि***

अधिनियम की धारा 37 के प्रावधान यह निर्धारित करने के लिए बिल्कुल भी प्रासंगिक नहीं हैं कि अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध या कोई भी अपराध जमानती या गैर-जमानती है। *उस उद्देश्य के लिए इस प्रावधान पर निर्भरता पूरी तरह से गलत है। यह ध्यान रखना उचित है कि अधिनियम की धारा 38 के अनुसार अधिनियम के तहत प्रत्येक अपराध को संहिता के अर्थ के तहत संज्ञेय बनाया गया है यानी एक पुलिस अधिकारी को अधिनियम के तहत अपराध के आरोपी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार है। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, अधिनियम की धारा 20 न केवल एक मजिस्ट्रेट को अधिकार देती है, कार्यकारी मजिस्ट्रेट और एक पुलिस अधिकारी, लेकिन कुछ अन्य व्यक्ति भी किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं यदि ऐसा व्यक्ति उस प्रावधान में उल्लिखित परिस्थितियों में कोई हथियार या गोला-बारूद ले जाता या ले जाता हुआ पाया जाता है और ऐसे हथियार या गोला-बारूद को जब्त भी कर लेता है। मेरा दृढ़ मत है कि अधिनियम की धारा 37 का खंड (बी) केवल उस स्थिति से निपटने के लिए अधिनियमित किया गया है जहां व्यक्ति को ऐसे अन्य*

व्यक्ति द्वारा गिरफ्तार किया जाता है और उस स्थिति में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति और जब्त किए गए हथियार या गोला-बारूद को निकटतम पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को सौंपना आवश्यक है और ऐसे अधिकारी को मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होने के लिए जमानतदारों के साथ या उसके बिना बांड भरने पर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को रिहा करने का अधिकार दिया गया है, लेकिन केवल इस कारण से यह नहीं माना जा सकता है कि अपराध या अधिनियम के तहत दंडनीय कोई भी अपराध जमानती है।

अधिनियम की धारा 37 में यह स्पष्ट नहीं है कि क्या होगा यदि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा अपेक्षित बांड निष्पादित करने और पर्याप्त जमानत देने में विफल रहता है और उसे मजिस्ट्रेट यानी कार्यकारी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। संहिता की धारा 436 के प्रावधानों के अनुसार, जमानती अपराध के आरोपी व्यक्ति को रिहा करने का अधिकार केवल एक न्यायालय को है, कार्यकारी मजिस्ट्रेट को नहीं। जब कार्यकारी मजिस्ट्रेट को ऐसे व्यक्ति को

जमानत पर रिहा करने का अधिकार नहीं दिया गया है, एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थिति के सीमित उद्देश्य के लिए पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा ऐसे व्यक्ति की रिहाई को ऐसे व्यक्ति की जमानत पर रिहाई कैसे कहा जा सकता है। केवल इसलिए कि अधिनियम की धारा 37 के खंड (बी) के तहत एक गिरफ्तार व्यक्ति की रिहाई के लिए एक विशेष प्रक्रिया प्रदान की गई है, जिसे अधिनियम की धारा 20 के तहत विशेष रूप से सशक्त कुछ व्यक्तियों द्वारा गिरफ्तार किया गया है, एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष अपनी उपस्थिति के सीमित उद्देश्य के लिए, संहिता की धारा 436 के अनुरूप प्रावधान नहीं किया जा सकता है। संहिता की धारा 436 किसी पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को जमानती अपराध के आरोपी व्यक्ति को जमानत पर रिहा करने के लिए अधिकृत करती है यदि ऐसे व्यक्ति को पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा बिना वारंट के गिरफ्तार या हिरासत में लिया जाता है। संहिता की धारा 436 के तहत एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को दी गई शक्ति

अधिनियम की धारा 37 के खंड (बी) के तहत उसे दी गई शक्ति से पूरी तरह से अलग है।

इसके अलावा, यदि कोई अधिनियम के तहत अपराध या किसी भी अपराध को केवल अधिनियम की धारा 37 के खंड (बी) के आधार पर जमानती निर्धारित करने के लिए जाता है,

कुछ बेतुके परिणाम अवश्य घटित होंगे क्योंकि अधिनियम के तहत कुछ अपराध बहुत गंभीर हैं और उनके लिए बहुत कड़ी सजा का प्रावधान है। अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के तहत गिनाए गए अपराध एक अवधि के लिए कारावास से दंडनीय हैं, जो तीन साल से कम नहीं होगी, लेकिन जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है; अधिनियम की धारा 25 (1) (ए) के तहत अपराध एक अवधि के लिए कारावास से दंडनीय है, जो पांच साल से कम नहीं होगी, लेकिन जिसे 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है, जबकि धारा 25 (1एए) के तहत अपराध के लिए कारावास की सजा हो सकती है, जो सात साल से कम नहीं होगी, लेकिन जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। यह कल्पना से परे है कि विधायिका

का इरादा था कि कड़ी सजा वाले ऐसे गंभीर अपराधों को जमानती बनाया जाए।

हालाँकि, इस उच्च न्यायालय की एक विद्वान एकल पीठ ने एक से अधिक मामलों में अधिनियम की धारा 37 पर भरोसा करते हुए माना है कि अधिनियम की धारा 3/25 के तहत अपराध जमानती है, लेकिन मैं इसका समर्थन करने और इसका पालन करने के लिए खुद को समझाने में असमर्थ हूं। चूंकि इसे संहिता और अधिनियम के सभी प्रासंगिक प्रावधानों पर ठीक से विचार किए बिना ऐसा माना गया है और इसलिए, विद्वान एकल पीठ द्वारा लिए गए विचार को गलत माना जाना चाहिए। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि यदि कोई निर्णय किसी वैधानिक प्रावधान की अनदेखी करके दिया जाता है तो उसे इंक्यूरियम के अनुसार माना जाएगा और इसे बाध्यकारी मिसाल के रूप में नहीं माना जा सकता है।

. . . . . .

इस सभी चर्चा का शुद्ध परिणाम यह है कि अधिनियम में स्पष्ट रूप से या निहित रूप से ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो यह प्रदान करता हो कि अधिनियम के तहत अपराध

या कोई भी अपराध जमानती है और इसके अभाव में संहिता के प्रावधान लागू होंगे। चूंकि वर्तमान मामले में जिस अपराध के लिए याचिकाकर्ता पर आरोप लगाया गया है, वह कारावास की सजा से दंडनीय है, जो तीन साल तक हो सकती है, इसे जमानती नहीं माना जा सकता है, जिससे याचिकाकर्ता को अधिकार के रूप में जमानत पर रिहा किया जा सके।

. . . . . ।"

10. इसके बाद याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने अधिनियम की धारा 37 और सीआरपीसी की धारा 436 के माध्यम से इस न्यायालय का रुख किया, जो इस प्रकार है:

<u>अधिनियम की धारा 37-</u>

"37. गिरफ़्तारी और तलाशी.—इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित को छोड़कर,—

(ए) इस अधिनियम के तहत या इसके तहत बनाए गए किसी भी नियम के तहत की गई सभी गिरफ्तारियां और तलाशी क्रमशः 36 [दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)] के प्रावधानों के अनुसार की जाएंगी, जो क्रमशः गिरफ्तारी और तलाशी से संबंधित हैं। उस संहिता के

तहत;

(बी) इस अधिनियम के तहत गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति और किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जब्त किए गए हथियार या गोला-बारूद, जो मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी नहीं है, को बिना देरी किए निकटतम पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को सौंप दिया जाएगा और वह अधिकारी-

(i) या तो उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने के लिए जमानतदारों के साथ या उसके बिना बांड भरने पर रिहा कर देगा और जब्त की गई चीजों को मजिस्ट्रेट के सामने उस व्यक्ति की उपस्थिति तक अपनी हिरासत में रखेगा, या

(ii) यदि वह व्यक्ति बांड निष्पादित करने और, यदि आवश्यक हो, पर्याप्त ज़मानत देने में विफल रहता है, तो उस व्यक्ति और उन चीज़ों को बिना किसी देरी के मजिस्ट्रेट के सामने पेश करें।

436. किन मामलों में जमानत लेनी चाहिए?

"(1) जब गैर-जमानती अपराध के आरोपी व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा बिना वारंट के गिरफ्तार या हिरासत में

लिया जाता है, या अदालत के सामने पेश किया जाता है या लाया जाता है, और किसी भी समय ऐसे अधिकारी की हिरासत में रहते हुए या ऐसे न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के किसी भी चरण में जमानत देने के लिए तैयार है, ऐसे व्यक्ति को जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा:बशर्ते कि ऐसा अधिकारी या न्यायालय, यदि वह उचित समझे, तो ऐसे व्यक्ति से जमानत लेने के बजाय, उसकी उपस्थिति के लिए जमानत के बिना एक बांड निष्पादित करने पर उसे मुक्त कर सकता है जैसा कि इसके बाद प्रदान किया गया है: बशर्ते कि इस धारा की किसी भी बात को धारा 116 या धारा 446ए की उप-धारा (3) के प्रावधानों को प्रभावित करने वाला नहीं माना जाएगा।"

11. इसके बाद, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने इस न्यायालय का ध्यान सीआरपीसी की अनुसूची I भाग II की ओर आकर्षित किया, जो कानूनों के खिलाफ अपराधों के वर्गीकरण से संबंधित है, जो इस प्रकार है:

अपराध	***संज्ञेय या गैर संज्ञेय***	***जमानतीय या गैर जमानती***	***अदालत विचारणीय***

यदि सज़ा मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक कारावास हो	संज्ञेय	गैर जमानती	सत्र न्यायालय
यदि 3 साल या उससे अधिक की कैद की सजा हो, लेकिन 7 साल से अधिक नहीं	संज्ञेय	गैर जमानती	प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट
यदि केवल 3 वर्ष से कम कारावास या जुर्माना से दंडित किया जा सकता है	गैर संज्ञेय	जमानती	कोई भी मजिस्ट्रेट

12. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने इस न्यायालय का ध्यान अधिनियम की धारा 25(1बी) की ओर भी आकर्षित किया है, जो अधिनियम की धारा 3 के तहत अपराध के लिए शस्त्र अधिनियम में सबसे कम सजा निर्धारित करता है, और इसे इस प्रकार पढ़ा जाता है:

“25(1बी) जो भी-

(एच) . . . .

(आई) . . . .

ऐसी अवधि के लिए कारावास से दंडनीय होगा जो एक वर्ष से कम नहीं होगी लेकिन जिसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

13. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने आगे कहा कि कई फैसलों में, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना कि तीन साल तक की कैद के लिए अन्य अधिनियमों के तहत दंडनीय अपराध अनुसूची- । सीआरपीसी के भाग -2 की दूसरी प्रविष्टि के अंतर्गत नहीं आते हैं, और इसलिए, गैर-जमानती हैं। इस संबंध में, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने मोहन लाल थापर बनाम वाई.पी.डाबारा, 2002(1) जेसीसी 460 और इंद्रजीत नागपाल बनाम राजस्व खुफिया निदेशक, आईएलआर (2005) दिल्ली 296 के पूर्ववर्ती कानून पर भरोसा किया।

14. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने यह भी प्रस्तुत किया कि माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय ने अविनाश भोंसले बनाम भारत संघ (सीआरएलए 1174/2007, 07.08.2007 को निर्णय लिया गया) में

इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाया था। यह मानते हुए कि अपराध, सजा, तीन साल की कैद तक बढ़ सकती है, गैर-जमानती हैं।

हालाँकि, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील के अनुसार, उसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अविनाश भोंसले बनाम भारत संघ (Criminal Appeal No.1138/2007, decided on 27.08.2007) मामले में माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए उपरोक्त दृष्टिकोण को निम्नलिखित शब्दों में खारिज कर दिया था:

"1. अनुमति दी गई।

2. रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री और सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की संशोधित धारा 135(1)(ii) से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि स्पष्ट रूप से अपराध जो आरोप लगाया गया है वह एक जमानती अपराध है और इस प्रकार मजिस्ट्रेट ने अपीलकर्ता को जमानत दे दी है। इसे देखते हुए हाई कोर्ट के आदेश को रद्द किया जाता है।

3. हम यह स्पष्ट करते हैं कि यदि विभाग किसी अन्य उल्लंघन या सीमा शुल्क अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम के उल्लंघन के संबंध में अपीलकर्ता के साथ आगे बढ़ना चाहता है जो उस अपराध से भिन्न हैं जिसके लिए अपीलकर्ता को गिरफ्तार किया गया था, विभाग ऐसे मामलों में कानून के अनुसार आगे बढ़ सकता है।

4. तद्नुसार अपील स्वीकार की जाती है।"

15. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने आगे कहा कि एक बार अधिनियम की धारा 37 को सीआरपीसी की धारा 436 के साथ पढ़ा जाए, तो अधिनियम के तहत अपराध, जिसमें तीन साल तक की कैद की सजा हो सकती है, संदेह से परे है।

16. इसके विपरीत, विद्वान लोक अभियोजक ने याचिकाकर्ताओं की ओर से दिए गए उपरोक्त प्रस्तावों का इस आधार पर जोरदार विरोध किया कि अन्य माननीय उच्च न्यायालयों के मामले कानून और माननीय उच्चतम न्यायालय सीमा शुल्क अधिनियम और कॉपीराइट अधिनियम से संबंधित थे, और इसमें शामिल शस्त्र अधिनियम के महत्वपूर्ण मुद्दे को कवर नहीं किया था।

17. विद्वान लोक अभियोजक ने प्रस्तुत किया कि विधायिका द्वारा बंदूक संस्कृति को जानबूझकर नियंत्रण में रखा गया है, और इस प्रकार, शस्त्र अधिनियम लाने के पीछे का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि अत्यधिक सावधानी बरतते हुए और कानून के मापदंडों के भीतर हथियार रखने की अनुमति दी जाए।

8. विद्वान लोक अभियोजक ने **अमर सिंह नरूका (सुप्रा)** के मामले में इस माननीय न्यायालय द्वारा दिए गए पहले के फैसले को फिर से दोहराया, और समझाया कि कैसे अधिनियम की धारा 37 केवल

मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी के अलावा अधिकारियों द्वारा गिरफ्तारी और तलाशी से संबंधित थी।

19. विद्वान लोक अभियोजक ने यह भी बताया कि अधिनियम की धारा 25(1बी) के प्रासंगिक प्रावधान में प्रयुक्त भाषा, अधिनियम की धारा 3 के तहत अपराध के लिए सजा से संबंधित है, एक वर्ष से कम कारावास की सजा नहीं है लेकिन कारावास तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार, विद्वान लोक अभियोजक के अनुसार, एक बार तीन साल की कैद की सीमा पूरी हो जाने पर, सीआरपीसी की अनुसूची । भाग ॥ भी वर्तमान मामले में लागू नहीं होगी क्योंकि यह केवल उन अपराधों से संबंधित है जो जमानती हैं, जिनमें तीन साल से कम कारावास की सजा हो। **विद्वान लोक अभियोजक द्वारा तीन साल से कम की कैद और तीन साल तक की बढ़ाई जा सकने वाली कैद के बीच की पतली रेखा को भी समझाया गया है।**

20. विद्वान अधिवक्ताओं और विद्वान लोक अभियोजकों द्वारा दी गई दलीलों पर विचारपूर्वक विचार करने के बाद, यह न्यायालय इस बात पर सहमत है कि हालाँकि दोनों विचारों को इस माननीय न्यायालय द्वारा विभिन्न निर्णयों में लिया गया है, जिन्हें इस न्यायालय के ज्ञान में भी लाया गया है, और प्रतिनिधि विचारों को यहाँ पुन: प्रस्तुत किया गया है, लेकिन यह न्यायालय खुद को उस दृष्टिकोण से सहमत होने

के लिए राजी करने में असमर्थ है, जैसा कि राम विलास @ बिल्लू (सुप्रा) में लिया गया था, क्योंकि अधिनियम की धारा 37 केवल गिरफ्तारी और तलाशी के लिए एक स्पष्ट प्रावधान है, और विशेष रूप से जमानत से संबंधित नहीं है। इस प्रकार, अधिनियम की धारा 37 पर भरोसा करना और यह तर्क देना कि धारा 37 (बी) के प्रावधान की भाषा के अनुसार, अधिनियम के तहत दंडनीय सभी अपराध जमानती हैं, कानून का एक दूरगामी अर्थ होगा।

21. राम विलास @ बिल्लू (सुप्रा) में दिए गए फैसले को मात्र पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि माननीय न्यायालय ने मुद्दे पर निर्णय किए बिना शस्त्र अधिनियम की धारा 3/25 के तहत अपराध को जमानती अपराध माना है, और वास्तव में केवल धारा 436 सीआर.पी.सी. पर विचार किया है।

22. अधिनियम की धारा 25(1बी) को पढ़ने पर, जिसका प्रासंगिक उद्धरण पहले ही यहां ऊपर उद्धृत किया जा चुका है, और जो अधिनियम की धारा 3 के तहत दंडनीय अपराध के लिए सजा का प्रावधान करता है, इस न्यायालय ने पाया कि उक्त प्रावधान के तहत सज़ा तीन साल की कैद तक बढ़ाई जा सकती है, और इस प्रकार, सीआरपीसी की अनुसूची । भाग ॥ को वर्तमान अपराधों को जमानती घोषित करने के रूप में नहीं माना जा सकता है, क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से जमानती

अपराधों के लिए सीमा के रूप में तीन साल से कम कारावास का उल्लेख है।

23. शस्त्र अधिनियम, हालांकि अपने आप में एक स्वतंत्र कानून है, लेकिन यह अपराधों की जमानती या गैर-जमानती के सवाल का कोई जवाब नहीं देता है, और इस प्रकार, अंतिम रूप से इसका निर्धारण करने के लिए, इस न्यायालय को सीआर.पी.सी. में निहित सामान्य प्रावधानों में जाना होगा, क्योंकि सीआर.पी.सी. की धारा 4 उप-धारा (2) यह प्रदान करती है, किसी भी कानून के तहत अपराधों को समान प्रावधानों के अनुसार निपटाया जाना चाहिए, ऐसे लेनदेन को विनियमित करने वाले अन्य अधिनियमों के अधीन, और चूंकि वर्तमान मामले में, शस्त्र अधिनियम जमानती या गैर-जमानती होने वाले अपराधों की प्रकृति को विनियमित नहीं कर रहा है, प्रश्न का उत्तर सीआरपीसी के ऐसे प्रावधानों के दायरे में सख्ती से दिया जाना चाहिए।

24. यह न्यायालय यह भी पाता है कि सीआरपीसी की अनुसूची । के भाग ।। में स्पष्ट रूप से उन अपराधों की परिकल्पना की गई है, जो तीन साल से कम कारावास से दंडनीय हैं और गैर संज्ञेय हैं, जमानती अपराध हैं।

25. अन्य माननीय उच्च न्यायालयों और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित पूर्ववर्ती कानून में कुछ मार्गदर्शन के लिए उपलब्ध

न्यायशास्त्र शस्त्र अधिनियम से संबंधित नहीं है, लेकिन सीमा शुल्क अधिनियम और कॉपीराइट अधिनियम पर व्यापक रूप से विचार किया गया है, जिसे शस्त्र अधिनियम की वर्तमान स्थिति से नहीं जोड़ा जा सकता है, क्योंकि अविनाश भोसले बनाम भारत संघ के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निपटाए गए अपराध - आपराधिक अपील संख्या 1138/2007 (सुप्रा) गैर-संज्ञेय अपराधों से संबंधित थे, जबकि अनुसूची । भाग ।। का प्रावधान शस्त्र अधिनियम से संबंधित मामलों के लिए फिट नहीं होगा, क्योंकि संबंधित अपराध न केवल संज्ञेय हैं (शस्त्र अधिनियम की धारा 38 के आधार पर), लेकिन तीन साल की कैद की दहलीज तक भी पहुंचता है और तीन साल से कम नहीं।

26. यह न्यायालय इस तथ्य से अवगत है कि व्यक्तियों, विशेष रूप से असामाजिक तत्वों के बीच विभिन्न अनधिकृत और अवैध हथियारों की आसान उपलब्धता ने, समाज में, एक बहुत ही गंभीर कानून और व्यवस्था की स्थिति पैदा कर दी है, जिसने कानून प्रवर्तन एजेंसियों के सामने आने वाली गंभीर चुनौतियों को कई गुना बढ़ा दिया है।

26.1. यह न्यायालय इस तथ्य से भी अवगत है कि उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पिछले तीन वर्षों में राजस्थान राज्य में 17,000 से अधिक अवैध हथियार बरामद किए गए हैं, और राज्य में अवैध हथियार प्राप्त करना एक आसान काम बन गया है।

राजस्थान पुलिस हर महीने करीब 500 अवैध हथियार बरामद करती है और मिली जानकारी के मुताबिक इनमें से 60 फीसदी हथियार मध्य प्रदेश से तस्करी कर लाए जाते हैं. प्राप्त जानकारी के अनुसार, अनधिकृत हथियार, जैसे देशी पिस्तौल (देसी कट्टा या तमंचा) की कीमत 500/- रुपये से 2,000/- रुपये तक होती है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, राजस्थान के ग्यारह जिले हैं जहां अवैध हथियारों का निर्माण और भंडारण किया जाता है और वहां से आपूर्ति की जाती है; झालावाड़ जिला सूची में शीर्ष पर है, और भरतपुर, धौलपुर, करौली, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, दौसा और राजसमंद जिले भी कतार में आते हैं।

26.2. राजस्थान राज्य में बंदूक प्रसार का डोमिनोज़ प्रभाव प्रासंगिक है, और यहां तक कि कानून और व्यवस्था की स्थिति पर भी इसका गंभीर प्रभाव पड़ता है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने नोट किया है कि आपराधिक मामलों में बड़ी संख्या में जब्ती बिना लाइसेंस वाले हथियारों की थी, कुल 74,877 हथियारों में से 71,135, इस प्रकार अनधिकृत हथियारों के खतरे को उसके वास्तविक परिमाण में दर्शाते हैं।

27. शस्त्र अधिनियम लाने का विधायी उद्देश्य इस प्रकार है: "हथियारों और गोला-बारूद से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करने के लिए एक अधिनियम। इसका उद्देश्य अवैध हथियारों

के प्रसार और परिणामी अपराधों को कम करना है।

28. अधिनियम की धारा 25 (1बी) अदालतों को सजा देने का अधिकार देती है, जिसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है, और इस प्रकार, तीन साल से कम कारावास की सजा भी वर्तमान मामले में लागू नहीं होगी। जैसा कि हम अधिनियम की धारा 20 और धारा 37 सहित अधिनियम के प्रावधानों से गुजरते हैं, यह देखा गया है कि मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी के अलावा अन्य व्यक्ति भी उक्त प्रावधान में उल्लिखित परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार करने और उससे हथियार या गोला-बारूद जब्त करने के लिए अधिकृत हैं। अधिनियम की धारा 37 के आशय को समझते समय ऐसे प्रावधानों को ध्यान में रखना होगा, यह समझना होगा कि उन गिरफ्तारियों और तलाशी के लिए, पुलिस स्टेशन या जमानत के लिए संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने की आवश्यकता अधिनियम की धारा 37 में निर्धारित की गई है, जो मोटे तौर पर केवल गिरफ्तारी और तलाशी से संबंधित है, और इसमें अपराधों की प्रकृति के जमानती या गैर-जमानती होने पर कोई प्रत्यक्ष कानून नहीं है। इस प्रकार, अधिनियम की धारा 37 भाग, शस्त्र अधिनियम के तहत अपराधों को जमानती घोषित करने में कोई मदद नहीं करती है।

29. अधिनियम की धारा 38, जो अधिनियम के तहत प्रत्येक अपराध को संज्ञेय अपराध बनाती है, इस प्रकार है:

"38. अपराधों का संज्ञेय होना।—इस अधिनियम के तहत प्रत्येक अपराध दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अर्थ के अंतर्गत संज्ञेय होगा।"

इस प्रकार, अधिनियम की धारा 38 सीमा शुल्क अधिनियम और कॉपीराइट अधिनियम से संबंधित मामलों में दिए गए निर्णय के साथ शस्त्र अधिनियम की विशिष्ट विशेषता है। सीआरपीसी की अनुसूची । भाग ॥ में, जमानती अपराधों की घोषणा को लागू करने के लिए, अपराध को गैर-संज्ञेय अपराध होना चाहिए, और तीन साल से कम के कारावास से दंडनीय होना चाहिए। चूँकि ऊपर उद्धृत अधिनियम की धारा 38 के अनुसार, अधिनियम के तहत प्रत्येक अपराध संज्ञेय है, इसलिए, यह जमानती अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि यह अनुसूची में ही स्पष्ट रूप से अलग है।

30. यदि अधिनियम की धारा 37, विशेष रूप से उसके खंड (2) को उस तरीके से पढ़ा जाता है, जैसा कि याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील चाहते हैं कि यह न्यायालय विश्वास करे, तो इसके परिणामस्वरूप शस्त्र अधिनियम के तहत सभी गंभीर अपराध हो सकते हैं। आजीवन कारावास के साथ-साथ अधिनियम के तहत दस साल और उससे

अधिक की सजा वाले अपराध, सभी जमानती अपराध बन जाएंगे।

31. इस प्रकार, इस न्यायालय का दृढ़ मत है कि सभी अपराध, जिसमें शस्त्र अधिनियम के तहत प्रदान की गई न्यूनतम सजा वाला अपराध भी शामिल है, जैसा कि धारा 25(1बी) के तहत निर्धारित है, जिसे तीन साल की कैद तक बढ़ाया जा सकता है, गैर-जमानती अपराध हैं।

32. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, यह न्यायालय शस्त्र अधिनियम के तहत सभी अपराधों को गैर-जमानती अपराध मानता है।

33. नतीजतन, सीआरपीसी की धारा 439 के तहत वर्तमान जमानत याचिकाएं खारिज कर दी जाती हैं, क्योंकि इस स्तर पर उन्हें योग्यता के आधार पर नहीं दबाया गया था।

34. यह न्यायालय वर्तमान निर्णय में बार के विद्वान वकीलों और विद्वान लोक अभियोजकों द्वारा प्रदान की गई बहुमूल्य सहायता के लिए सराहना दर्ज करता है।

न्यायाधीश, (डॉ.पुष्पेन्द्र सिंह भाटी)

(अनुवाद एआई टूल: SUVAS के माध्यम से अनुवादक की मदद से किया गया है)

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय का उपयोग वादी को अपनी भाषा में समझने के लिए सीमित उपयोग के लिए किया जाता है और इसका उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त होगा।